International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 28-04-2026, Accepted: 29-05-2026, Published: 13-06-2026
Volume 12, Issue 2, 2026, Page No. 176-179

ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मौसमी रोजगार सरंचना (उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

सुश्मिता सिंह[1], मृदुला मिश्रा[2]
[1] शोध छात्रा, अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/ijhr.2026.12.2.12161

सारांश
यह शोध–पत्र जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मौसमी रोजगार संरचना का अध्ययन प्रस्तुत करता है। जौनपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जहाँ अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और आजीविका के लिए कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर रहती है। जिले में लघु एवं सीमांत कृषकों की प्रधानता तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की बड़ी संख्या मौसमी रोजगार की समस्या को और अधिक गंभीर बनाती है। कृषि उत्पादन का स्वरूप मुख्य रूप से खरीफ (धान), रबी (गेहूँ) और आंशिक रूप से जायद फसलों पर निर्भर करता है, जिसके कारण वर्ष भर श्रम की मांग समान रूप से नहीं रहती।
मौसमी रोजगार संरचना से अर्थ है कि वर्ष के विभिन्न समयों में श्रम की मांग, उपलब्धता और आय के स्तर में होने वाले उतार–चढ़ाव से है। जौनपुर जिले में खरीफ की फसल का मौसम (जून–सितंबर) के दौरान होता है जिसमें धान की रोपाई, निराई–गुड़ाई और कटाई के समय श्रम की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। इस अवधि में पुरुषों के साथ–साथ महिला श्रमिकों की भागीदारी भी दिखाई देती है। दैनिक मजदूरी दरों में अस्थायी बढ़ोत्तरी देखी जाती है और श्रमिकों को अपेक्षाकृत अधिक कार्य–दिवस उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार रबी फसल का मौसम (अक्टूबर–मार्च) तक रहता है जिसमें गेहूँ की बुवाई और कटाई के समय श्रम की मांग बढ़ती है, किंतु कृषि के बढ़ते यंत्रीकरण जैसे–ट्रैक्टर, थ्रेसर और हार्वेस्टर के कारण श्रम की कुल आवश्यकता में आंशिक कमी भी देखी जा रही है।
मौसमी रोजगार संरचना का प्रभाव केवल आय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एवं मानवीय विकास के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता है। अनियमित आय के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण पर व्यय में कमी आती है। महिला श्रमिकों को कम मजदूरी और अस्थायी कार्य की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई परिवारों में बच्चों को भी श्रम में लगना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। इस प्रकार मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण गरीबी के चक्र को स्थायी रूप प्रदान करती है।
अतः कहा जा सकता है कि जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मौसमी रोजगार संरचना केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक विकास से जुड़ा व्यापक प्रश्न है। समन्वित ग्रामीण विकास नीतियों और स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है।

मूल शब्दः मौसमी रोजगार, कृषि श्रमिक, प्रवास, आय–असमानता, जौनपुर जनपद

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, और कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण कृषि श्रमिक न केवल उत्पादन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे ग्रामीण समाज की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को भी प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित जौनपुर जिला एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ अधिकतर जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ लघु एवं सीमांत जोतों की बहुलता, भूमिहीन श्रमिकों की बड़ी संख्या तथा परंपरागत कृषि पद्धतियाँ मौसमी रोजगार की समस्या को जटिल बनाती हैं।
मौसमी रोजगार संरचना से तात्पर्य वर्ष के विभिन्न कालचक्रों में कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कार्य–दिवसों, मजदूरी दरों तथा आय के स्तर में होने वाले परिवर्तन से है। कृषि का स्वभाव ही ऐसा है कि यह फसल–चक्र और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जौनपुर जिले में मुख्य रूप से खरीफ (धान), रबी (गेहूँ) और सीमित रूप से जायद फसलें उगाई जाती हैं। धान की रोपाई और कटाई के समय श्रम की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, जबकि मध्यवर्ती अवधि में कार्य के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसी प्रकार रबी की बुवाई और कटाई के दौरान श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार मिलता है, किंतु शेष महीनों में रोजगार का अभाव देखा जाता है।
यह असंतुलित रोजगार संरचना ग्रामीण कृषि श्रमिकों के जीवन में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करती है। जिन परिवारों के पास स्वयं की भूमि नहीं है, वे पूरी तरह दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। जब कृषि कार्य उपलब्ध नहीं होते, तब उन्हें अन्य रोजगार की तलाश करनी पड़ती है। इसी कारण जौनपुर जिले से निकटवर्ती शहरों जैसे– वाराणसी तथा राज्य की राजधानी लखनऊ की ओर अस्थायी प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह प्रवास प्रायः कम समय के लिए होता है और निर्माण कार्य, लघु उद्योगों या अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के खोज के रूप में सामने आता है।
मौसमी बेरोजगारी केवल आय की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विकास से भी जुड़ी हुई है। अनियमित आय के कारण ग्रामीण परिवारों में ऋण ग्रस्तता बढ़ती है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है तथा स्वास्थ्य एवं पोषण पर व्यय कम होता है। महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी और असुरक्षित कार्य में वि ाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मौसमी रोजगार संरचना ग्रामीण गरीबी और सामाजिक विषमता को स्थायी रूप देने में भूमिका निभाती है।
सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार की समस्या को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से कृषि के ऑफ–सीजन में ग्रामीण श्रमिकों को न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। जौनपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, जल संरक्षण एवं भूमि सुधार जैसे कार्यों में श्रमिकों को रोजगार मिलता है। तथापि, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक

चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनका प्रभाव उनकी प्रभावशीलता पर पड़ता है।

इस शोध–पत्र की प्रस्तावना का उद्देश्य जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मौसमी रोजगार संरचना की पृष्ठभूमि, स्वरूप एवं उससे उत्पन्न सामाजिक–आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट करना है। यह शोध इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि वर्ष के विभिन्न कालखंडों में रोजगार की उपलब्धता किस प्रकार श्रमिकों की आय, जीवन–स्तर और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। साथ ही, यह भी विचारणीय है कि किन नीतिगत उपायों के माध्यम से मौसमी बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है।

संबंधित शोध साहित्य का अध्ययनः

उपरोक्त विषय में कुछ विद्वानों ने जौनपुर जिले की मौसमी कृषि रोजगार के संबंध में अध्ययन किया जो निम्न प्रकार है–

W. Arthur Lewis (1954) Lewis ने द्वि–क्षेत्रीय मण्डल में बताया कि परंपरागत कृषि क्षेत्र में श्रम की अधिकता रहती है, जिससे छिपी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। उन्होंने माना कि कृषि क्षेत्र में श्रम का मौसमी स्वरूप आय–अस्थिरता को बढ़ाता है। उनके अनुसार ग्रामीण श्रमिकों का गैर–कृषि क्षेत्र की ओर स्थानांतरण विकास का संकेत है।

Gunnar Myrdal (1957) Myrdal ने 'सर्कुलर एंड क्यूम्यूलेटिव कॉजेशन' सिद्धांत के माध्यम से ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी के चक्र को स्पष्ट किया। उनके अनुसार मौसमी बेरोजगारी विकासशील देशों में संरचनात्मक असमानता का परिणाम है।

Theodore W. Schultz (1964) Schultz ने पारंपरिक कृषि में मानव पूंजी के अभाव को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और शिक्षा के अभाव में कृषि श्रमिक मौसमी बेरोजगारी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते।

Amartya Sen (1975) ने 'एंटाइटलमेंट अप्रोच' के माध्यम से स्पष्ट किया कि रोजगार की अनियमितता खाद्य–सुरक्षा को प्रभावित करती है। उनके अनुसार ग्रामीण श्रमिकों की आय–अस्थिरता अकाल जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती है।

Pranab Bardhan (1984) ने ग्रामीण श्रम बाजार की अपूर्णताओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि मौसमी मांग–आपूर्ति असंतुलन मजदूरी दरों को प्रभावित करता है।

R. S. Deshpande (2002) देशपांडे ने कृषि क्षेत्र में आय असमानता और श्रम शोषण को मौसमी रोजगार से जोड़ा।

T. Haque (2005) ने भूमि सुधार और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को रोजगार स्थिरता हेतु आवश्यक बताया।

Himanshu (2011) ने ग्रामीण मजदूरी दरों के उतार–चढ़ाव को मौसमी कारकों से संबंधित बताया।

C.H. Hanumantha Rao (1988) के अनुसार हरित क्रांति के बाद भी भूमिहीन श्रमिकों की मौसमी बेरोजगारी समाप्त नहीं हुई। कृषि वृद्धि का लाभ सीमांत श्रमिकों तक समान रूप से नहीं पहुँचा।

Jean Drèze (1990) ने ग्रामीण रोजगार योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने माना कि ऑफ–सीजन में सार्वजनिक कार्यक्रम श्रमिकों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करते हैं।

V. M. Dandekar (1971) दांडेकर ने ग्रामीण गरीबी और कृषि श्रमिकों की आय–असमानता पर प्रकाश डाला। उन्होंने मौसमी रोजगार को ग्रामीण निर्धनता का मूल कारण बताया।

C. H. Hanumantha Rao (1984) ने कृषि विकास और रोजगार सृजन के संबंध को रेखांकित किया। उनके अनुसार सिंचाई विस्तार से मौसमी बेरोजगारी घटाई जा सकती है।

Angus Deaton (1997) ने उपभोग और आय–अस्थिरता के संबंध का विश्लेषण किया। उनके अनुसार मौसमी आय–परिवर्तन ग्रामीण परिवारों के उपभोग स्तर को प्रभावित करते हैं।

Timothy Besley (1995) ने सार्वजनिक नीति और ग्रामीण संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजनाएँ आय–सुरक्षा में सहायक हो सकती हैं।

Christopher Barrett (2008) ने ग्रामीण आजीविका विविधीकरण को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार गैर–कृषि रोजगार मौसमी अस्थिरता को कम कर सकता है।

Peter Hazell (2010) ने कृषि उत्पादकता और ग्रामीण रोजगार के बीच संबंध स्पष्ट किया। उन्होंने माना कि छोटे किसानों की आय वृद्धि से श्रमिकों के अवसर बढ़ते हैं।

Jules Pretty (2002) ने टिकाऊ कृषि को ग्रामीण रोजगार का दीर्घकालिक आधार माना। पर्यावरणीय संतुलन से वर्ष भर रोजगार की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

Angus Deaton (2013) ने गरीबी और उपभोग पर अपने अध्ययन में बताया कि आय की मौसमी अस्थिरता ग्रामीण परिवारों के जीवन–स्तर को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

अध्ययन् की आवश्यकता एवं महत्व

जौनपुर जैसे कृषि–प्रधान जिले में वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार की अधिकता तथा अन्य महीनों में तीव्र अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इस असंतुलित रोजगार संरचना के कारण आय–अस्थिरता, ऋणग्रस्तता, कुपोषण, शिक्षा में बाधा तथा अस्थायी प्रवास जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जौनपुर जिले में लघु एवं सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है। ऐसे परिवारों के पास आय के वैकल्पिक स्रोत सीमित होते हैं। कृषि के ऑफ–सीजन में रोजगार की कमी उन्हें शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास के लिए विवश करती है। यह प्रवास सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

वर्तमान समय में कृषि का यंत्रीकरण, जलवायु परिवर्तन, वर्षा की अनिश्चितता तथा भूमि–खंडन जैसी समस्याएँ भी मौसमी रोजगार को प्रभावित कर रही हैं। इन परिवर्तनों के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना किस प्रकार बदल रही है और उसका सामाजिक–आर्थिक प्रभाव क्या है।

साथ ही, सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ विशेषकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) मौसमी बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करती हैं। यह अध्ययन यह मूल्यांकन करने में सहायक होगा कि इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव क्या है और किन सुधारों की आवश्यकता है।

▪ अध्ययन् का महत्व

यह अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

- यह अध्ययन कृषि श्रमिकों की आय, मजदूरी दरों और कार्य–दिवसों के वितरण को स्पष्ट करेगा। इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि वर्ष भर रोजगार संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है।
- मौसमी बेरोजगारी का प्रभाव, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर पड़ता है। यह अध्ययन ग्रामीण समाज की वास्तविक जीवन–परिस्थितियों को उजागर करेगा।
- स्थानीय प्रशासन और नीति–निर्माताओं के लिए यह शोध उपयोगी सिद्ध होगा। इससे रोजगार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कृषि विविधीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ेगा।
- यह अध्ययन ग्रामीण विकास की समग्र रणनीति तैयार करने में सहायक होगा, जिसमें कृषि के साथ–साथ गैर–कृषि रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दिया जा सके।

- यह शोध ग्रामीण श्रम बाजार, मौसमी बेरोजगारी और प्रवास के अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार प्रदान करेगा। भविष्य के शोधार्थियों के लिए यह संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा।
- जौनपुर जैसे कृषि–प्रधान क्षेत्रों से रोजगार के अभाव में श्रमिकों का अस्थायी प्रवास निकटवर्ती शहरों–जैसे वाराणसी और लखनऊ की ओर बढ़ता है। यह प्रवास ग्रामीण पारिवारिक संरचना और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। यह अध्ययन प्रवास के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कर क्षेत्रीय संतुलित विकास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो अनावश्यक प्रवास को रोका जा सकता है और स्थानीय विकास को गति मिल सकती है।
- जौनपुर जैसे पूर्वांचल क्षेत्र में रोजगार संरचना पर विशेष अध्ययन हालांकि कम हुए हैं। अतः यह शोध क्षेत्र–विशेष की समस्याओं को प्रकाश में लाकर क्षेत्रीय असमानताओं को समझने में योगदान देगा।

इस प्रकार, यह अध्ययन आर्थिक, सामाजिक, नीतिगत और क्षेत्रीय विकास अन्य सभी पायदानों में अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा जौनपुर जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने और सुदृढ़ करने की दिशा में सार्थक योगदान प्रदान करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मौसमी रोजगार संरचना का विस्तृत अध्ययन करना।

- जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मौसमी रोजगार संरचना का विश्लेषण करना।
- वर्ष के विभिन्न कृषि मौसमों (खरीफ, रबी एवं जायद) में रोजगार की उपलब्धता और कार्य–दिवसों के वितरण का अध्ययन करना।
- मौसमी रोजगार के कारण आय में होने वाले उतार–चढ़ाव का मूल्यांकन करना।
- कृषि के ऑफ–सीजन में उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति का परीक्षण करना।
- मौसमी बेरोजगारी के कारण ग्रामीण श्रमिकों के अस्थायी प्रवास की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
- कृषि के यंत्रीकरण एवं तकनीकी परिवर्तन का श्रम मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्ले ाण करना।
- महिला कृषि श्रमिकों की भागीदारी तथा उनकी मजदूरी संबंधी स्थिति का अध्ययन करना।
- ग्रामीण कृषि श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ऋण आदि) पर मौसमी रोजगार के प्रभाव का परीक्षण करना।
- सरकारी योजनाओं विशेषकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की भूमिका और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- कृषि विविधीकरण, कौशल विकास तथा गैर–कृषि रोजगार के माध्यम से वर्षभर रोजगार सृजन की संभावनाओं का विश्लेषण करना।
- मौसमी रोजगार संरचना के आधार पर ग्रामीण विकास हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाऐं

1. जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार की उपलब्धता फसल–चक्र (खरीफ, रबी, जायद) के अनुसार महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित होती है।
2. खरीफ एवं रबी मौसम में कार्य–दिवसों की संख्या जायद एवं मध्यवर्ती अवधि की तुलना में अधिक होती है।
3. मौसमी रोजगार की अस्थिरता के कारण कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय में महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव पाया जाता है।
4. कृषि के ऑफ–सीजन में रोजगार के अभाव से ग्रामीण श्रमिकों में अस्थायी प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है।
5. कृषि के बढ़ते यंत्रीकरण से पारंपरिक श्रमिकों के लिए कार्य–दिवसों की संख्या में कमी आई है।
6. महिला कृषि श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी तथा कम कार्य–दिवस प्राप्त होते हैं।
7. जिन श्रमिक परिवारों को गैर–कृषि आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, उनमें मौसमी आय–अस्थिरता का प्रभाव अपेक्षाकृ त कम होता है।
8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत उपलब्ध रोजगार कृषि के ऑफ–सीजन में आय–अस्थिरता को आंशिक रूप से कम करता है।
9. सिंचाई सुविधाओं और बहुफसली प्रणाली वाले क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है।
10. मौसमी रोजगार संरचना का ग्रामीण कृषि श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन–स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना के प्रकार

व्यवहार में वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों में कई प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं जो निम्नलिखित हैं:

- सकारात्मक उपकल्पना
- नकारात्मक उपकल्पना
- शून्य उपकल्पना

किसी भी शोधकार्य को सुविधाजनक बनाने हेतु शून्य परिकल्पना अनुसंधान हेतु सर्वोत्तम होती है।

शून्य परिकल्पना

इसमें यह मानकर चलते हैं कि जो चर जिसमें सम्बन्ध ज्ञात करने जा रहे हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है। NULL जर्मन भाशा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शून्य, अतः इस परिकल्पना को शून्य परिकल्पना कहते हैं।
शून्य परिकल्पना को नकारात्मक उपकल्पना इस अर्थ में मानते हैं कि प्रयुक्त चरों में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह निर्देशन रहित होती है। अनुसंधानकर्ता को स्वीकार व अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है।
शोध में परिकल्पनाओं की पुष्टिकरण के लिए कुछ शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया है जिसकी सार्थकता की जाँच सहसम्बन्ध तथा क्रांतिक अनुपात द्वारा की गयी है।

अनुसंधान विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।
वर्णनात्मक पक्ष के अंतर्गत कृषि श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, कार्य–दिवसों का वितरण एवं मजदूरी दरों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
विश्लेषणात्मक पक्ष में मौसमी रोजगार, आय–अस्थिरता, प्रवास तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र के रूप में जौनपुर जिले का चयन उसके कृ षि–प्रधान स्वरूप, ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता तथा श्रम–आधारित कृषि व्यवस्था के कारण किया गया है। यह जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग (पूर्वांचल) में स्थित है और ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जौनपुर जिला

भौगोलिक रूप से गंगा–गोमती दोआब क्षेत्र में अवस्थित है तथा इसकी जलवायु उप–उष्णकटिबंधीय है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान तथा वर्षा ऋतु में मानसूनी वर्षा प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो कृषि उत्पादन और श्रम की मांग को सीधे प्रभावित करती हैं।

अध्ययन् की सीमाएँ

- यह अध्ययन केवल जौनपुर जिले के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। अतः इसके निष्कर्षों को संपूर्ण उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों पर पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता।
- अध्ययन एक निश्चित समयावधि (एक कृषि वर्ष पर आधारित है। वर्ष विशेष की वर्षा, जलवायु या बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण रोजगार की स्थिति में असामान्य उतार–चढ़ाव संभव है, जो दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को पूर्णतः नहीं दर्शाता।
- अध्ययन में सीमित संख्या में कृषि श्रमिक परिवारों को शामिल किया गया है। नमूना आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण संपूर्ण जनसंख्या की विविधता पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सकती।

आँकड़ों के स्रोत

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है–

प्राथमिक स्त्रोतः चयनित ग्रामों के कृषि श्रमिक परिवारों से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी संकलित की गई। इसमें कार्य–दिवसों की संख्या, मजदूरी दर, आय, प्रवास, सामाजिक स्थिति आदि से संबंधित प्रश्न शामिल थे।

द्वितीयक स्त्रोतः जनसंख्या, कार्यबल भागीदारी एवं ग्रामीण–शहरी संरचना संबंधी आँकड़ों के लिए। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, सरकारी प्रकाशन, शोध–पत्र, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं से प्राप्त किए गए।

निश्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन ''उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विशेष संदर्भ में ग्रामीण कृषि मौसमी श्रमिकों की रोजगार संरचना'' के संदर्भ में हैं, इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना मूलतः मौसमी स्वरूप की है, जिसमें वर्ष के विभिन्न कृषि मौसमों के अनुसार श्रम की मांग में महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव पाया जाता है। खरीफ और रबी फसलों के समय विशेषकर धान की रोपाई एवं कटाई तथा गेहूँ की बुवाई एवं मड़ाई के दौरान श्रम की मांग अधिक रहती है, जिससे श्रमिकों को पर्याप्त कार्य–दिवस एवं अपेक्षाकृत बेहतर आय प्राप्त होती है। इसके विपरीत जायद एवं मध्यवर्ती अवधि में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय कमी देखी जाती है, जिससे आय–अस्थिरता और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि भूमिहीन एवं सीमांत कृषि श्रमिक मौसमी बेरोजगारी से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। आय के सीमित स्रोत, ऋण पर निर्भरता तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी उनके जीवन–स्तर को अस्थिर बनाती है। कृषि के ऑफ–सीजन में अनेक श्रमिक निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों की ओर अस्थायी प्रवास करते हैं, जो आर्थिक आवश्यकता का परिणाम है। यह प्रवास अल्पकालिक आय तो प्रदान करता है, किंतु पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मौसमी रोजगार की समस्या केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक एवं विकासात्मक चुनौती भी है।

संदर्भ सूची

1. Besley, Timothy. Property Rights and Investment Incentives: Theory and Evidence from Ghana. Journal of Political Economy, vol. 103, no. 5, 1995, pp. 903–937.
2. Desai, A. R. भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र,रावल पब्लिकेशन्स, 2004.
3. Datt, Ruddar, and K. P. M. Sundharam. भारतीय अर्थव्यवस्था,एस.चंद एण्ड कंपनी, 2018.
4. Reardon, Thomas, *et al*. Rural Nonfarm Employment and Incomes in Latin America. World Development, vol. 29, no. 3, 2001, pp. 395–409.
5. Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776. Methuen & Co., 1904 edition.
6. Thorner, Daniel, and Alice Thorner. भूमि और श्रम संबंध : भारत का अध्ययन,ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002.
7. Singh, Surjit. ग्रामीण श्रम बाजार और रोजगार संरचना, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, 2011.
8. Hazell, Peter. The Future of Small Farms: Trajectories and Policy Priorities. World Development, vol. 38, no. 10, 2010, pp. 1349–1361.
9. Binswanger Hans P, Mark R. Rosenzweig. Behavioural and Material Determinants of Production Relations in Agriculture. Journal of Development Studies, vol. 32, no. 1, 1995, pp. 1– 25.
10. Singh, Katar. ग्रामीण विकास के सिद्धांत और व्यवहार, सेज पब्लिकेशन्स, 2009.
11. Breman, Jan. पदचिन्हः असंगठित श्रम और असुरक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस, 2013.
12. Singh, Katar. ग्रामीण विकास के सिद्धांत और व्यवहार,सेज पब्लिकेशन्स, 2009.
13. Jha, Utsa Patnaik. कृषि विकास और ग्रामीण निर्धनता,सेज पब्लिकेशन्स, 2007.
14. Government of India. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005. Ministry of Rural Development, 2005.
15. Pretty, Jules. Agri-Culture: Reconnecting People, Land and Nature. Earthscan Publications, 2002.